वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नीति–विषयक दस्तावेज के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना भारत सरकार की कार्यसूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन, उत्पादकता तथा लाभप्रदता में वृद्धि करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थल–विशिष्ट, किफायती तथा जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की सहभागिता आधारित अनुसंधान की दिशा में अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कुलपति की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समितियाँ गठित की हैं। अन्य सभी कुलपति तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक, सम्बद्ध क्षेत्र के निदेशक, अटारी, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से प्रत्येक से एक नामिती एवं संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। राज्य–विशिष्ट दस्तावेज विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान, इन रणनीतियों पर चर्चा करने तथा इनमें संशोधन करने के लिए परिषद के स्तर पर कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। जिनमें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, प्रोफेसर रमेश चंद, संबंधित विभागों के सचिवों तथा गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य हितधारकों सहित प्रख्यात विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया ताकि इन रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए विशेषज्ञों के व्यापक और विषद अनुभव का लाभ उठाया जा सके। इन दस्तावेजों में राज्यों की सभी कृषि पारिस्थितिकियों के लिए रणनीतियां शामिल की गई हैं और ऐसा करते समय बागवानीए पशुधन, मात्स्यिकी, कृषि वानिकी तथा सस्योपरान्त प्रसंस्करण क्रियाओं के विकास के लिए राज्यों में विद्यमान संभावनाओं और क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है। इन दस्तावेजों में उक्त प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने के लिए रणनीतियां उपलब्ध करवाने के साथ–साथ में उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी, गुणवत्ता में सुधार आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

संबंधित राज्यों की सभी कृषि पारिस्थितिकियों में कार्यान्वयन हेतु राज्यवार तैयार इन दस्तावेजों को माननीय कृषि मंत्री जी तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्तर पर राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समितियां इन रणनीतियों को कार्यान्वित करने एवं आवश्यक तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इनके कार्यान्वयन की निगरानी में संलग्न हैं। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान राज्यों को इन रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए सलाह दे रही है तथा गैर सरकारी संगठनों एवं राज्य एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों को इस कार्य से जोड़ कर कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से कुछ चयनित गांवों में कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों नें किसानों की आय को दोगुना करने हेतु महत्वपूर्ण पहल की हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी के मॉडल के तहत डीसीएस श्रीराम लिमिटेड (डीएसएल) नई दिल्ली के साथ मिलकर किसानों की आय को दोगुना करने हेतु गन्ना क्षेत्र की क्षमता का दोहन करते हुए दो जिलों के आठ गांवों में सभी 2028 किसान परिवारों की आय को दोगुना करने के लिए चार चीनी मिलों के कमान क्षेत्र में संयुक्त उद्यम शुरू किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों में भी ऐसे ही मॉडल विकसित और प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।

वर्तमान संस्करण एक सार दस्तावेज है जो विस्तृत राज्य–विशिष्ट दस्तावेजों से विकसित किया गया है तथा इसमें विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए जाने हेतु दृष्टिकोण, प्रमुख रणनीतियां तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग और कुछ मामलों में कुछ चयनित प्रकरण अध्ययन (केस स्टडीज)/सफलता गाथाएं भी संक्षेप में शामिल की गई हैं। इस दस्तावेज में निर्दिष्ट रणनीतियों में एक ही समय पर कई कार्य निष्पादित करते हुए कृषि कार्य को कृषि–उद्यम में बदलने की दृष्टि से कृषि–व्यवसाय पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने तथा मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करने से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से इतर (नॉन फार्म) रोजगार के अवसरों का सृजन करने में सहायता मिलेगी। हमें पूर्ण आशा है कि नीति निर्माताओं, किसानों, फील्ड में कार्यरत विस्तार कार्मिकों और संबंधित वैज्ञानिकों के अतिरिक्त विभिन्न विकास एजेंसियां एवं विभाग इस दस्तावेज को उपयोगी पाएंगे और यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सपने को साकार करने में सार्थक भूमिका निभाने में सक्षम होगा।

BRIEF NOTE ON THE STRATEGY DOCUMENT FOR DOUBLING FARMERS' INCOME BY 2022

Doubling of farmers' income by 2022 is the most important agenda of government of India. With this in view, ICAR has intensified efforts towards farmers' participatory research to develop and scale up location specific, cost effective and climate resilient technologies to enhance agricultural production, productivity and profitability in the agriculture sector and increase farmers' income. To realise this, Indian Council of Agricultural Research constituted State Level Coordination Committees (SLCCs) headed by a Senior Vice Chancellor of an Agricultural University in each state. All the other Vice Chancellors and the ICAR Directors, Director, ATARI of the concerned region, one nominee each of the related central ministries as well as the senior representatives of the concerned State Departments as the members of the Committee. During the process of the development of the state specific documents, a series of review meetings at the level of the Council were held to discuss and revise the strategies during which eminent authorities including Prof. M.S. Swaminathan, Prof. Ramesh Chand, Secretaries of line departments and other stakeholders including NGOs were also invited to bring in wide ranging expertise to fine-tune the strategies. The documents provide strategies for all the agro-ecologies of the States keeping into mind the scope and potential for development of Horticulture, Livestock, Fisheries, Agro-forestry and Post-harvest processing in the states. The documents focus on enhanced production, reduction of cost, improvement in quality besides providing strategy for scaling out these technologies.

The state wise documents were subsequently provided to the state governments from the levels of Hon'ble Minister and DG, ICAR for implementing in all agro-ecologies of their respective states. The state level coordination committees have been asked to oversee and implementation in close coordination with the respective state Governments to provide necessary technical help and guidance to implement these strategies. Indian Council of Agricultural Research through its Research Institutes and State Agricultural Universities is advising states to implement these strategies. ICAR, on its part is implementing the action plan in selected villages through KVKs and ICAR Research Institutes by involving other stakeholders including NGOs and the state agencies. ICAR Institutes notably Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow took initiatives for doubling farmers' income in Public Private Partnership Model to harness the potential of sugarcane sector towards doubling farmers' income, and initiated a joint venture with DCM Shriram Limited (DSL), New Delhi in command areas of four sugar mills in 2017 to double income of all 2028 farm families in eight villages of two districts by introducing technological, human resource and developmental interventions. Similar models are being developed & promoted in other ICAR Institutes.

The present volume is a summary document developed from the detailed state specific documents and includes in brief the approaches, major strategies and technology interventions included to be implemented in different states at times supported by few case studies/ success stories. The strategies in the document focus on increased emphasis on agri-business through transforming farming into agri-enterprises performing multiple functions at one point of time. Encouraging processing and building value chains would help create non-farm jobs in rural areas. We sincerely hope that the document will be found useful by various development agencies and departments besides policy planners, farmers, field extension workers and concerned scientists alike, and will play a meaningful role towards realising this very important dream of our Hon'ble Prime Minister.